



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936

No. 104]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

**दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014
(2014 का 3)**

सं. 1-6/2014-बी एंड सीएस.—भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो—

- (क) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा
- (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड 3 के उप-खंड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 39 का.आ. 44 (अ)] तथा 45(अ)) के तहत प्रकाशित हुई थी,—

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 06) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः :—

- (1) इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 (2014 का 3) कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश अप्रैल, 2014 के प्रथम दिन से लागू होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 06) (जिसे इसमें आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 3 में "दिसंबर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचालित तथा चार प्रतिशत से अनधिक राशि की वृद्धि, और ऐसी बढ़ाई गई राशि के सात प्रतिशत से अनधिक राशि की और वृद्धि, अधिकतम सीमा होगी," शब्दों और संख्याओं के लिए "दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन)

आदेश, 2014 के लागू होने से पूर्व प्रचालित जो कि पन्द्रह प्रतिशत से अधिक की राशि से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अधिकतम सीमा होगी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल टैरिफ आदेश की अनुसूची में,—

(क) भाग-1 में “गैर-कैस क्षेत्रों में केबल ऑपरेटर या मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर को फ्री-टु-एयर चैनल और पे-चैनल, दोनों को ट्रांसमिट या रि-ट्रांसमिट करने के लिए सब्सक्राइबर [खंड 3 के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट] द्वारा देय प्रभार” शीर्षक के अंतर्गत सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट और रि-ट्रांसमिट किए जाने वाले पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों की संख्या		कॉलम (2) के अंतर्गत उल्लिखित पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए प्रथम टेलीविजन कनेक्शन हेतु प्रति माह सब्सक्राइबर द्वारा देय प्रभारों की अधिकतम राशि (सभी करों को छोड़कर)		
(1)	(2)		(3)		
	पे-चैनल	फ्री-टु-एयर चैनल	एक्स श्रेणी के शहर तथा पहले के ए श्रेणी के शहर *	वाई श्रेणी के शहर, पहले के ए श्रेणी के शहरों को छोड़कर *	जेड श्रेणी के शहर, नगर तथा अन्य घर
	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)
1	बीस पे-चैनलों तक	न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल	एक सौ सतानवे रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ तिहतर रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ साठ रुपए मात्र से अधिक नहीं
2	बीस से अधिक तथा तीस पे-चैनलों तक	न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल	दो सौ छियालीस रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ नौ रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ सतानवे रुपए मात्र से अधिक नहीं
3	तीस से अधिक तथा पैंतालीस पे-चैनलों तक	न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल	दो सौ नवासी रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ छियालीस रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ अट्ठाइस रुपए मात्र से अधिक नहीं
4	पैंतालीस से अधिक पे-चैनल	न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनल	तीन सौ बीस रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ सत्तर रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ छियालीस रुपए मात्र से अधिक नहीं

(ख) भाग-II में, सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत, “बयासी रुपए मात्र” शब्दों के स्थान पर “चौरानवे रुपए मात्र” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

परमेश्वरन एन., प्रधान सलाहकार (बी एण्ड सीएस)

[विज्ञापन III/4/असा./142/13]

टिप्पणी 1 : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2014 (2014 का 3) के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट किया गया है।

टिप्पणी 2 : मूल विनियमों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2004, अधिसूचना संख्या: 1-29/2004-बीएण्डसीएस के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 अधिसूचित किया गया तथा इन्हें बाद में दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1-29/2004-बीएण्डसीएस, दिनांक 01 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1-29/2004-बीएण्डसीएस, दिनांक 29 नवंबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 1-13/2005-बीएण्डसीएस, दिनांक 07 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-2/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 24 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-2/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 31 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-13/2005-बीएण्डसीएस, दिनांक 21 नवंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-19/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 1-1/2007-बीएण्डसीएस, दिनांक 26 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 1-31/2008-बीएण्डसीएस और अधिसूचना संख्या 1-2/2014-बीएण्डसीएस, 10 फरवरी, 2014 के माध्यम से संशोधित किया गया।

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. वर्ष 2004 में प्राधिकरण ने केबल सेवाओं के लिए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) दिनांक 01 अक्टूबर, 2004 जारी किया गया था, जिसमें केबल सब्सक्राइबर द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों/प्रसारकों तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा प्रसारकों को अदा किए जाने वाले फ्री-टु-एयर तथा पे-चैनलों, दोनों के संबंध में 26 दिसंबर, 2003 को प्रचलित केबल प्रभारों को, करों को छोड़कर ऐसे प्रभारों पर अधिकतम सीमा बनाई गई थी। दिनांक 01 अक्टूबर, 2004 को भादूविप्रा ने टीवी चैनलों के प्रसारण एवं वितरण के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें भी भेजी थीं, जिसमें अन्य बातों के साथ ही साथ, यह उल्लेख किया गया कि मुद्रास्फीति का समायोजन करने के लिए उपर्युक्त टैरिफ आदेश में निर्धारित की गई अधिकतम सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

2. तदनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के आधार पर क्रमशः 01 दिसंबर, 2004 के दूसरे टैरिफ संशोधन आदेश तथा 29 नवंबर, 2005 के तीसरे टैरिफ संशोधन आदेश के द्वारा केबल प्रभारों में मुद्रास्फीति से संबंध क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई। केबल प्रभारों में मुद्रास्फीति संबंधी यह वृद्धि क्रमशः 01 जनवरी, 2005 और 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी होनी थी। तथापि, एक उपभोक्ता संगठन द्वारा दायर एक अपील पर टीडीसेट द्वारा 20/12/2005 को स्थगनादेश जारी किए जाने के कारण 4 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित तीसरे संशोधन आदेश को लागू नहीं किया जा सका। तदुपरांत, टीडीसेट ने दिनांक 22/12/2006 के अपने आदेश के द्वारा स्थगनादेश को रद्द कर दिया।

3. भादूविप्रा ने केबल प्रभारों के लिए अधिकतम सीमा को जारी रखते हुए, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007 के अपने आठवें टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्रों में केबल प्रभारों में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दी, उन सेवा प्रदाताओं को प्रभार में वृद्धि की अनुमति प्रदान की जिन्होंने टीडीसेट के 22 दिसंबर, 2006 के स्थगनादेश को रद्द करने के बाद प्रभारों में वृद्धि नहीं की थी। तदुपरांत, दिनांक 26 दिसंबर, 2008 को टैरिफ आदेश में किए गए नौवें संशोधन के माध्यम से मुद्रास्फीति में 7 प्रतिशत की और वृद्धि की अनुमति दी गई। यह वृद्धि, दिनांक 01 जनवरी, 2009 से प्रभावी हुई।

4. इस तरह से, दिनांक 01 अक्टूबर, 2004 का मूल टैरिफ आदेश लागू होने से अब तक तीन मुद्रास्फीति वृद्धियों (1) दिनांक 01 जनवरी, 2005 से 7 प्रतिशत, (2) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 4 प्रतिशत, और (3) दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 7 प्रतिशत, की अनुमति अभी तक दी जा चुकी है। आज तक अनुमत की गई मुद्रास्फीति संबंध वृद्धियों का सारांश नीचे सारणी-क में दिया गया है:-

सारणी-क : अभी तक अनुमत की गई मुद्रास्फीति संबद्ध का सारांश												
क्र. सं.	जिस तारीख से मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि की अनुमति दी गई	प्रदत्त मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि हेतु कवर की गई अवधि और संवादी डब्ल्यूपीआई			प्रदत्त वास्तविक वृद्धि की मात्रा	कुल मुद्रास्फीति संबद्ध अनुमति (दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 तक)	डब्ल्यूपीआई में वृद्धि (दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 तक)	डब्ल्यूपीआई वृद्धि का प्रभावी प्रतिशत (पास-श्रू) जो कि दिया गया	अभ्युक्ति			
				डब्ल्यूपीआई								
1	1.1.2005	से	दिसंबर-03	176.8	7%	19%	30%	63%	डब्ल्यूपीआई डाटा 1993-94 की श्रेणी के अनुसार			
		तक	दिसंबर-04	188.8								
2	1.1.2006	से	दिसंबर-04	188.8	4%							
		तक	दिसंबर-05	197.2								
3	1.1.2009	से	दिसंबर-05	197.2	7%							
		तक	दिसंबर-08	229.7								

5. नीचे वर्णित कारणों से विगत पांच वर्षों में वृद्धि (मुद्रास्फीति के आधार पर) की अनुमति नहीं दी गई। कई सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ आदेश में 8वें संशोधन को माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसेट) में 2007 की अपील संख्या 10(सी) से 15(सी) के द्वारा चुनौती दी गई तथा माननीय टीडीसेट ने अपने दिनांक 15 जनवरी, 2009 के आदेश के द्वारा टैरिफ आदेश में किए गए उक्त संशोधन को निरस्त कर दिया। भादूविप्रा की अपील (दिनांक 2009 के सीए नंबर 829-833 भादूविप्रा बनाम सेट डिस्कवरी एवं अन्य) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13 मई, 2009 के अंतरिम आदेश में माननीय टीडीसेट के उक्त आदेश पर रोक लगा दी तथा प्राधिकरण को निर्देशित किया कि वह टैरिफ निर्धारण के लिए नए सिरे से कार्रवाई कर, माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तदनुसार, प्राधिकरण द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए कार्रवाई की गई तथा उसे दिनांक 21 जुलाई, 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में एक मसौदा टैरिफ आदेश भी संलग्न किया गया था, जिसमें अन्य के साथ ही साथ टैरिफ की अधिकतम सीमा में 9 प्रतिशत मुद्रास्फीति संबंध वृद्धि का भी प्रावधान था।

6. उक्त मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2009 से लंबित है। इस कारण से विगत पांच वर्षों में टैरिफ आदेश में मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि का समायोजन नहीं किया गया है। इस आधार पर, प्राधिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीए नंबर 829-833 भादूविप्रा बनाम सेट डिस्कवरी एवं अन्य के मामले में इन्टरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) संख्या: 71-75/2014 दायर की तथा माननीय न्यायालय से टैरिफ आदेश की समीक्षा करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आईए की अनुमति प्रदान की और अपने आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2014 में निम्नलिखित कहा :-

“ इन आवेदनों में दिए गए कथनों का अवलोकन करने पर, अपीलीय प्राधिकारी को अनुमति दी जाती है कि वह मुद्रास्फीति के समायोजन हेतु अधिकतम टैरिफ सीमा की समीक्षा करे तथा उसे, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करे ।”

7. अब तक पालन की गई पद्धति के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित मासिक डब्ल्यूपीआई डाटा के आधार पर, अब प्राधिकरण द्वारा दिसंबर, 2008 से फरवरी, 2014 के लिए डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन की गणना की गई। जनवरी, 2008 से माहवार डब्ल्यूपीआई डाटा को संकलित किया गया तथा वह परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है। इस डब्ल्यूपीआई डाटा से, दिसंबर, 2008 से फरवरी, 2014 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति 43.69 प्रतिशत के बराबर बैठती है।

8. अभी तक प्रदान की गई मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धियों का विश्लेषण, ऊपर सारणी-क में किया गया है। प्रासंगिक कारकों पर विचार करने से यह देखा जा सकता है कि दिसंबर, 2003 से दिसंबर, 2008 की अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि प्राधिकरण द्वारा मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि में केवल 19 प्रतिशत की अनुमति दी गई। इस प्रकार, पास-थ्रू लगभग 63 प्रतिशत रहा है। इसलिए, विचाराधीन अवधि के लिए केवल इसी तरह के पास-थ्रू की अनुमति देना उपयुक्त होगा। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर विचाराधीन अवधि (दिसंबर, 2008 से मार्च, 2014) के लिए अनुमत की जाने वाली मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि की गणना की गई तथा उसे नीचे सारणी-ख में दिया गया है:-

सारणी—ख : दिसंबर, 2008 से मार्च, 2014 की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि						
मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि की अनुमति देने की तिथि	मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि की अनुमति देने हेतु कवर की गई अवधि और संवादी डब्ल्यूपीआई			डब्ल्यूपीआई के अनुसार मुद्रास्फीति की मात्रा	संवादी अवधि के लिए डब्ल्यूपीआई में 63 प्रतिशत पास—थ्रू वृद्धि को लेते हुए मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि में प्रदान की गई अनुमति की कुल मात्रा	अभ्युक्ति
1.4.2014	से	दिसंबर—08	124.5	43.69%	27.5%	1. 2004—05 श्रेणी के अनुसार डब्ल्यूपीआई डाटा। 2. केवल फरवरी, 2014 तक का ही डब्ल्यूपीआई डाटा उपलब्ध है। अतः मार्च, 2014 के लिए फरवरी, 2014 के डाटा को लिया गया है।
	तक	मार्च—14	178.9			

9. प्राधिकरण का मत है कि एक ही बार में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि करना बाजार के लिए उपयुक्त नहीं होगा, उपभोक्ताओं को इसे समायोजित करने हेतु समय की आवश्यकता होगी। अतः प्राधिकरण ने इस वृद्धि को दो किस्तों में लागू करने का निर्णय लिया है। 15 प्रतिशत की प्रथम किस्त, दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगी, जिसे इस टैरिफ आदेश में शामिल किया गया है। पृथक टैरिफ आदेश के माध्यम से, दिसंबर, 2008 से मार्च, 2014 की अवधि हेतु, मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि की शेष दूसरी किस्त 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगी, जिसे बाद में जारी किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि इससे सभी हितधारकों को इस वृद्धि के समायोजन हेतु पर्याप्त और उचित समय प्राप्त होगा।

10. अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2007 के टैरिफ संशोधन आदेश में, प्राधिकरण ने पे-चैनलों की संख्या और शहरों/नगरों के वर्गीकरण के आधार पर विशिष्ट टैरिफ की अधिकतम सीमा (सीलिंग) को भी विनिर्दिष्ट किया था। तदनुसार, 15 प्रतिशत मुद्रास्फीति संबद्ध वृद्धि को हिसाब में लेकर, इस प्रकार की अधिकतम सीमा (सीलिंग) की गणना उपभोक्ता स्तर के लिए की गई तथा उसे टैरिफ आदेश में सारणीबद्ध किया गया है। उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं की सुविधा के मद्देनजर, टैरिफ की अधिकतम सीमा (सीलिंग) को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।

परिशिष्ट-1

माहवार – डब्ल्यूपीआई डाटा

(स्रोत :- कार्यालय आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट)

डब्ल्यूपीआई												
वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
2014	178.9	178.9										
2013	170.3	170.9	170.1	171.3	171.4	173.2	175.5	179	180.7	180.7	181.5	179.2
2012	158.7	159.3	161	163.5	163.9	164.7	165.8	167.3	168.8	168.5	168.8	168.8
2011	148	148.1	149.5	152.1	152.4	153.1	154.2	154.9	156.2	157	157.4	157.3
2010	135.2	135.2	136.3	138.6	139.1	139.8	141	141.1	142	142.9	143.8	146
2009	124.4	123.3	123.5	125	125.9	126.8	128.2	129.6	130.3	131	132.9	133.4
2008	117.5	119	121.5	123.5	124.1	127.3	128.6	128.9	128.5	128.7	126.9	124.5

2004-05 के लिए डब्ल्यूपीआई डाटा—100

फरवरी 2014 से आगे का डब्ल्यूपीआई डाटा उपलब्ध नहीं है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES (SECOND) TARIFF
(ELEVENTH AMENDMENT) ORDER, 2014

(No. 3 of 2014)

No. 1-6/2014 – B & CS.—In exercise of the powers conferred by sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39,—

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 [S.O. 44 (E) and 45 (E)] dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii),—

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004), namely:—

- (1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Eleventh Amendment) Order, 2014 (3 of 2014).
- (2) This Order shall come into force on the 1st day of April, 2014.
- In clause 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004) (hereinafter referred to as the principal tariff order), for the words and figures “prevalent as on 1st day of December, 2007, and increased by an amount not exceeding four per cent and further increased by an amount not exceeding seven per cent of such increased amount shall be the ceiling,” the words and figures “prevalent before the coming into force of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Eleventh Amendment) Order, 2014, and increased by an amount not exceeding fifteen per cent. shall be the ceiling ” shall be substituted.
- In the Schedule to the principal tariff order,—

- (a) in PART I, for the Table under the heading “Charges payable by a subscriber (referred to in sub-clause (a) of clause 3) to the cable operator or multi system operator transmitting or re-transmitting both Free to Air channels and Pay channels in Non-CAS areas.”, the following Table shall be substituted, namely:—

Serial Number	Number of pay channels and Free to Air channels to be transmitted or re-transmitted through the cable television network.		Maximum amount of charges payable by a subscriber per month for first television connection (exclusive of all taxes) for Pay channels and Free to Air channels mentioned under column (2)		
(1)	(2)		(3)		
	Pay channels	Free to Air channels	X Class cities and erstwhile A Class cities*	Y Class cities excluding erstwhile A Class cities*	Z Class cities, towns and other habitations
	2(a)	2(b)	3(a)	3(b)	3(c)
1.	Up to twenty pay channels	minimum thirty Free to Air channels	Not exceeding rupees one hundred and ninety seven only.	Not exceeding rupees one hundred and seventy three only.	Not exceeding rupees one hundred and sixty only.
2.	More than twenty and up to thirty pay channels	minimum thirty Free to Air channels	Not exceeding rupees two hundred and forty six only.	Not exceeding rupees two hundred and nine only.	Not exceeding rupees one hundred and ninety seven only.
3.	More than thirty and up to forty five pay channels	minimum thirty Free to Air channels	Not exceeding rupees two hundred and eighty nine only.	Not exceeding rupees two hundred and forty six only.	Not exceeding rupees two hundred and twenty eight only.
4.	More than forty five pay channels	minimum thirty Free to Air channels	Not exceeding rupees three hundred and twenty only.	Not exceeding rupees two hundred and seventy only.	Not exceeding rupees two hundred and forty six only.

- (b) in PART II, under column (2) of the Table, for the words “Rupees eighty two only”, the words “Rupees ninety four only” shall be substituted.

PARAMESWARAN N., Principal Advisor (B&CS)

[ADVT. III/4/Exty./142/13]

Note 1.—The Explanatory Memorandum annexed to this Order explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Eleventh Amendment) Order, 2014 (3 of 2014).

Note 2.—The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 (6 of 2004) was published vide notification no. 1-29/ 2004-B&CS dated the 1st October, 2004 and subsequently amended vide notifications no. 1-29/ 2004-B&CS dated the 26th October, 2004, no. 1-29/ 2004-B&CS dated the 1st December, 2004, No. 1-13/ 2005-B & CS dated the 29th November, 2005, No. 1-2/ 2006-B&CS dated the 7th March, 2006, no. 1-2/ 2006-B & CS dated the 24th March, 2006, No. 1-13/ 2005-B&CS dated the 31st July, 2006, No. 1-19/ 2006-B&CS dated the 21st November, 2006, No. 1-1/2007-B&CS dated the 04th October, 2007, No. 1-31/2008-B&CS dated the 26th December 2008 and No. 1-2/2014 - B&CS dated 10th February 2014.

Annexure

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. In 2004, the Authority had issued the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 (6 of 2004) dated 1st October 2004, for cable services, wherein cable charges excluding taxes, payable by Cable Subscribers to Cable Operators, Cable Operators to Multi System Operators/ Broadcasters, Multi System Operators to Broadcasters, prevailing as on 26th December 2003 in respect of both free to air and pay channels were made as the ceiling. On 1st October 2004, the Authority also sent its recommendations to the Government on Issues relating to

Broadcasting and Distribution of TV channels in which, *inter alia*, it was stated that the ceilings prescribed by the above said tariff order shall be reviewed periodically to make adjustments for inflation.

2. Accordingly, inflation linked increases of 7% and 4% in the cable charges were permitted through the Second Tariff Amendment Order of 1st December 2004 and the Third Tariff Amendment Order of 29th November 2005 respectively, based on the movement of the wholesale price index (WPI). These inflation linked increases in the cable charges were to be effective from 1st January 2005 and 1st January 2006, respectively. However, the Third Tariff Amendment Order relating to the 4% increase could not be brought into operation as the Hon'ble TDSAT stayed it on 20th December 2005 on an appeal filed by a consumer organisation. Subsequently, through its order dated 22nd December 2006, TDSAT vacated the stay.
3. Through the Eighth Amendment to the Tariff Order, dated 4th October 2007, TRAI, while continuing the ceiling on the cable charges, permitted a 4% increase in the cable charges in those cases in which service providers had not increased the charges after the stay was vacated by Hon'ble TDSAT on 22nd December 2006. Subsequently, vide Ninth Amendment dated 26th December 2008 to the Tariff Order, another inflationary hike by 7% was allowed. This hike became effective from 1st January 2009.
4. Thus, after coming into force of the principal tariff order of 1st October 2004, three inflationary hikes (i) 7% w.e.f. 1st January 2005, (ii) 4% w.e.f. 1st January 2006, and (iii) 7% w.e.f. 1st January 2009 have so far been allowed. Table A below summarises the inflation linked hikes permitted till date.

Table A : Summary of inflation linked hikes allowed till date											
Sr. No.	Date from which Inflation linked hike allowed	Period covered for allowing the inflation linked hike and corresponding WPI			Quantum of actual hike allowed	Effective total inflation linked hike allowed (Dec. 2003 till Dec. 2008)	Increase in WPI (from Dec 2003 till Dec 2008)	Percentage pass -through	Remarks		
				WPI							
1	1.1.2005	From	Dec-03	176.8	7%	19%	30%	63%	WPI data as per 1993-94 series.		
		To	Dec-04	188.8							
2	1.1.2006	From	Dec-04	188.8	4%						
		To	Dec-05	197.2							
3	1.1.2009	From	Dec-05	197.2	7%						
		To	Dec-08	229.7							

5. No increase (on grounds of inflation) has been allowed for the past five years, for the reasons discussed below. The Eighth Amendment to the Tariff Order was challenged by several service providers vide appeal Nos. 10(c) to 15(c) of 2007 in the Hon'ble Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) which, in its judgment dated 15th January 2009, struck down the said amendment to the tariff order. On TRAI's appeal (CA no. 829-833 of 2009 TRAI Vs Set Discovery and Ors), Hon'ble Supreme Court, in its interim order dated 13th May 2009, stayed the said Hon'ble TDSAT judgment and directed the Authority to carry out *de novo* tariff determination exercise and submit a report to it. The Authority carried out the exercise and submitted the same in the Hon'ble Supreme Court on 21st July 2010. In this report, a draft tariff order was also attached which, amongst others, had a provision for 9% inflation linked hike in the tariff ceilings.

6. The said matter has been pending in the Hon'ble Supreme Court since 2009. In effect this means that there has been no inflation linked adjustments in the Tariff Order during the past five years. In this background, the Authority approached the Hon'ble Supreme Court and filed an Interlocutory Application (I.A.) Nos. 71-75 of 2014 in CA no. 829-833 of 2009 in the case of TRAI Vs Set Discovery and Ors, and sought permission of the Hon'ble Court to review the Tariff Order. The Hon'ble Supreme Court allowed the IA and in its order dated 28th February 2014 held as under:
- “On going through the averments in these applications, the Appellate Authority is permitted to review the tariff ceiling to make adjustment for inflation and notify the same, in exercise of its powers conferred under section 11(2) of the TRAI Act, 1997.”*
7. In line with the past practice, the Authority has now worked out the change in the WPI from December 2008 to February 2014, based on the monthly WPI data maintained by the Ministry of Commerce and Industry. The month-wise WPI data since January 2008 has been compiled and placed at Appendix I. From this WPI data, the inflation works out to be equal to 43.69% for the period December 2008 to February 2014.
8. The inflation linked hikes provided till date have been analysed in Table A above. It can be seen that while the WPI moved up by 30% during the period from December 2003 till December 2008, taking the relevant factors into considerations, the effective inflation linked hike permitted by the Authority was 19%. Thus, the pass-through was around 63%. Therefore, it would be only appropriate that a similar pass-through is permitted for the period under consideration. Keeping in line with the above analysis, the inflation linked hike to be permitted for the period under consideration (from December 2008 to March 2014) has been worked out and is presented in Table B below.

Table B: Inflation linked hike to be provided covering the period from Dec 2008 to Mar 2014						
Date from which Inflationary hike allowed	Period covered for allowing the inflation linked hike and the corresponding WPI			Quantum of Inflation as per WPI	Total quantum of inflation linked hike to be allowed taking pass through as 63% of hike in WPI for the corresponding period	Remarks
1.4.2014	From	Dec-08	124.5	43.69%	27.5%	1. WPI data as per 2004-05 series. 2. WPI data is available only up to Feb. 2014. Hence, data of Feb. 2014 has been taken for Mar. 2014.
	To	Mar-14	178.9			

9. The Authority is of the view that a hike to the tune of 27.5% in a single go would not be appropriate for the market; consumers need some time to adjust. Therefore, the Authority has decided that this hike should be implemented in two installments. The first installment of 15% shall be effective from 1st April 2014 which has been incorporated in this Tariff Order. The second installment for the remaining inflation linked increase, for the period from December 2008 to March 2014, shall be made effective from 1st January 2015 thorough a separate tariff order to be issued subsequently. This is expected to give enough and reasonable time to all the stakeholders to adjust to these hikes.
10. In its tariff amendment order dated 4th October 2007, the Authority had prescribed specific tariff ceilings at consumer level based on the number of pay channels and classification of cities/towns. Accordingly, to account for the 15% inflation linked hike, similar tariff ceilings at the consumer level have been worked out and tabulated in the tariff order. The tariff ceilings have been rounded-off to the nearest rupee from the point of view of convenience of the consumers and service providers.

Appendix I

Month-wise WPI Data

Year	WPI											
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
2014	178.9	178.9										
2013	170.3	170.9	170.1	171.3	171.4	173.2	175.5	179	180.7	180.7	181.5	179.2
2012	158.7	159.3	161	163.5	163.9	164.7	165.8	167.3	168.8	168.5	168.8	168.8
2011	148	148.1	149.5	152.1	152.4	153.1	154.2	154.9	156.2	157	157.4	157.3
2010	135.2	135.2	136.3	138.6	139.1	139.8	141	141.1	142	142.9	143.8	146
2009	124.4	123.3	123.5	125	125.9	126.8	128.2	129.6	130.3	131	132.9	133.4
2008	117.5	119	121.5	123.5	124.1	127.3	128.6	128.9	128.5	128.7	126.9	124.5

(Source: Website of the Office of Economic Adviser to the Government, Ministry of Commerce and Industry)

WPI Data for 2004-05 = 100

WPI data not available beyond February 2014.